[2015] 1 एस. सी. आर. 667

यू. पी. राज्य

बनाम

ओम प्रकाश

(आपराधिक अपील संख्या 1187/2006)

13 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायाधिपति एन. वी. रमना]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 / 149 – 5 व्यक्तियों की नृशंस हत्या और 7 व्यक्तियों को तेज धार वाले हथियारों/लाठियों से गंभीर चोट - एक-दूसरे से संबंधित सभी आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर गांव के चुनावों में अपनी हार का बदला लेने के लिए पीड़ितों पर हमला किया - जब पीड़ितों ने खुद को बचाने की कोशिश की एक झोपड़ी में शरण ले रहे थे, उसमें आग लगा दी गई - भागने की कोशिश करने वाले पीड़ितों के साथ भी मारपीट की गई - घटना शाम 5 बजे की है पर्याप्त रोशनी में - घायल चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की स्वतंत्र गवाह और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई - गवाहों की उपस्थिति और पीड़ितों द्वारा आरोपियों की पहचान पर विवाद नहीं - चोटों की प्रकृति और आरोपियों से हथियारों की बरामदगी से पता चला कि यह एक बड़ी अप्रिय घटना थी और अभियुक्तों ने सक्रिय रूप से अपराध में भाग लिया - अभियोजन ने उचित संदेह से परे अभियुक्तों का अपराध साबित कर दिया - दोषसिद्धि को बरकरार रखा - जहां तक सजा का सवाल है, अभियुक्त केवल बदला लेने की भावना से उत्पीड़ित थे और उन्मत्त होकर भाग रहे थे - हत्या की क्रूरता सभी शमन करने वाले कारकों के साथ देखा जाना चाहिए - हालाँकि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई आपत्तिजनक परिस्थितियाँ अपीलकर्ता को दोषी ठहराती हैं, लेकिन मामले की सभी

शमन करने वाली और गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करने के बाद, मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है। दुर्लभ मामले - उनके सुधार और पुनर्वास की आशा है - साथ ही, उनके हाथों ऐसे आपराधिक कृत्यों की पुनरावृत्ति जो समाज को और कमजोर बनाती है, वह भी स्पष्ट नहीं है - अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मौत की सजा को संशोधित करने में हाई काउट सही था विचारण न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास/दंड की सजा सुनाई गई।

न्यायालय ने राज्य और आरोपी की अपील खारिज कर दी और अभिनिर्धारित किया-

1. अभियुक्त का आपराधिक इरादा उचित संदेह से परे साबित हुआ। जब आरोपी नंबर 7 की पत्नी ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, जिसमें वह हार गई, तो आरोपी व्यक्तियों के समूह ने आरोप लगाया कि पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपी नंबर 7 की पत्नी के पक्ष में कोई मतदान नहीं किया गया और पीड़ित पक्ष को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। तदनुसार, चुनाव में उस विफलता का बदला लेने के लिए, आरोपी पक्ष को होली के दिन शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करने का यह उपयुक्त अवसर लगा, जिसमें पांच निर्दोष व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कई अन्य को घायल कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से पता चला कि आरोपी नंबर 7 पूरे समय आरोपी पक्ष को पीड़ित पक्ष पर हमला करने के लिए उकसा रहा था, अन्य आरोपियों ने अपराध में भाग लिया था। जब असहाय पीड़ितों ने एक कोठरी (छोटा कमरा) में शरण ली, तो आरोपियों ने अपना बदला लेने के लिए, कोठरी के दरवाजे काटने की कोशिश की और ऐसा करने में असफल होने पर, उन्होंने छप्पर पर मिट्टी का तेल डाला और कोठरी को जला दिया। जली हुई चोटें और पीड़ितों की मौत। चोटों की प्रकृति और आरोपियों के पास से हथियारों की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि यह एक बड़ी अप्रिय घटना थी और आरोपियों ने अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया

था। सभी आरोपी एक-दूसरे से संबंधित थे और उन्होंने घातक हथियारों से लैस एक मजबूत समूह बनाया और गांव के चुनावों में अपनी हार का बदला लेने के लिए पीड़ितों पर हमला किया। आरोपी द्वारा दी गई यह दलील कि घटनास्थल पर आरोपी की पहचान करना मुश्किल है, जबकि अपराध में लगभग 35 लोगों की भागीदारी थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि घटना शाम 5.00 बजे हुई थी। मार्च के महीने में पर्याप्त प्रकाश में और निर्विवाद रूप से, आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पीडब्लू1, पीडब्लू2, पीडब्लू4 घायल चश्मदीद गवाह थे जिनके बयानों की पुष्टि पीडब्लू3, एक अन्य स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य से की गई थी। इन गवाहों ने स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह से आरोपी व्यक्तियों ने अपराध किया। इस प्रकार घटना के समय गवाहों की उपस्थिति और पीड़ितों द्वारा आरोपियों की पहचान पर विवाद नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तों के कब्जे से घातक हथियारों की बरामदगी ने घातक कृत्य में उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका की दृढ़ता से पुष्टि की। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त का अपराध साबित कर दिया। [पैरा 10, 19,21, 221, [676-सी-ई; 682-डी-ई; 683-बी-ई, एफ-एच]

मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470:1983 (3) एससीआर 413; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980)2 एससीसी 684; राम पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2003) 7 एससीसी 141 - पर निर्भर।

2. मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले, अपराधी की परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मृत्युदंड की सजा केवल उसी मामले में दी जा सकती है जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास देना पूरी तरह से अपर्याप्त है।

गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों की बैलेंस शीट तैयार करनी होगी और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी नंबर 7 की पत्नी जो चुनाव हार गई थी, उसके पक्ष में वोट न देने के लिए ग्रामीणों से बदला लेने के लिए, आरोपी पक्ष ने पीड़ितों पर हमला किया। करीब दस महीने पहले घटना की तिथि ग्राम प्रधान पद के चुनाव हुए थे चुनाव के समय और घटना की तारीख के बीच लंबे समय के अंतराल को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपियों ने चुनाव में अपने पक्ष में वोट न देने का बदला लेने के स्पष्ट उद्देश्य से पीड़ितों पर हमला किया। एक गाँव के दो समूहों के बीच झड़प को अनुपात में बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता है। हालाँकि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई आपत्तिजनक परिस्थितियाँ अपीलकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराती हैं, लेकिन मामले की सभी कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करने के बाद, यह मामला बनता है दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आते। उनके सुधार और पुनर्वास के लिए आशा की किरण है। ट्रायल जज द्वारा दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में संशोधित करने में उच्च न्यायालय सही था। [पैरा 28, 33 से 35] [685-डी-एफ; 687-डी बी-डी; 688-बी-ई]

नील कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 5 एससीसी 766:2012 (5) एससीआर 696; हरीश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (12) एससीसी 56: 2011 (14) एससीआर 921; आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1995 एससी 264: 1994 (4) पूरक। एससीआर 353; संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य (2010) 9 एसईसी 747: 2010 (13) एससीआर 901 - पर भरोसा किया गया।

वाद कानून संदर्भित

1983(3)एस सी आर 413	संदर्भित	पैरा 12

(1980)2 एस सी सी 684	संदर्भित	पैरा 18
(2003)7 एस सी सी 141	संदर्भित	पैरा 18
2012(5)एस सी आर 696	संदर्भित	पैरा 28
1983(3)एस सी आर 413	संदर्भित	पैरा 28
(1980)2 एस सी सी 684	संदर्भित	पैरा 28
2011(14)एस सी आर 921	संदर्भित	पैरा 29
1994(4)पूरकएस सी आर 353	संदर्भित	पैरा 30
2010(13)एस सी आर 901	संदर्भित	पैरा 31

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की आपराधिक अपील संख्या 1187

2004 की आपराधिक अपील संख्या 713 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.09.2005 से।

साथ

आपराधिक अपील संख्या 2006 की 1186 और 2007 की 773

अपीलकर्ता के लिए राज सिंह राणा, अनुराग सिंह, अनिल कुमार मिश्रा, नरेंद्र सिंह यादव, के एल जंजानी, हरबंस लाल बजाज।

प्रतिवादी के लिए गौरव भाटिया, एएजी, अमीत सिंह, अलका सिन्हा, यू.जायसवाल, अनुव्रत शर्मा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

न्यायाधिपति एन.वी. रमना

1. ये अपीलें 23 जनवरी, 2004 को पारित फैसले और आदेश से उत्पन्न विभिन्न आपराधिक अपीलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 23 सितंबर, 2005 के एक आम आक्षेपित फैसले से उत्पन्न हुई हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम), जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

2. शिकायतकर्ता लालता प्रसाद द्वारा थाना बुखारा, जिला पीलीभीत, उ.प्र. में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 10 मार्च, 2001 को आरोप लगाया कि जब वह हेम राज, मोती राम कुंदन, शिव चरण लाल पुत्र हई शंकर और उसके पिता देवी राम के साथ अपने क्रशर पर बैठे थे और रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होली का त्योहार मना रहे थे। नंबर 7 राम स्वरूप पुत्र होरी लाल अन्य अभियुक्तों के साथ विभिन्न प्रकार के हथियार लेकर आया और उन पर हमला कर दिया। उनके हमले के पीछे का मकसद यह था कि घटना से लगभग दस महीने पहले आरोपी नंबर 7 (राम स्वरूप) की पत्नी लमरती देवी ने ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और हार गई थी. प्रधान और राम स्वरूप (आरोपी नंबर 7) ने ग्रामीणों को उसकी पत्नी को इस पद पर निर्वाचित न करने का खामियाजा भुगतने की धमकी दी थी। इसलिए, वह ग्रामीणों से बदला लेना चाहता था। राम स्वरूप के साथ आए अन्य आरोपियों में जगन लाल (आरोपी नंबर 2) बंदूक से लैस थे, राम भरोसे (आरोपी नंबर 32) पौनिया को ले जा रहे थे, अशोक कुमार (आरोपी नंबर 31) थे),कुंवर सेन (अभियुक्त संख्या 26), लाला राम (अभियुक्त संख्या 22) और राम स्वरूप पुत्र दल चंद (अभियुक्त संख्या 2) सभी देशी पिस्तौल से लैस थे। पतिराम (अभियुक्त क्रमांक 12), होरी लाल(अभियुक्त क्रमांक 28), ओम प्रकाश (अभियुक्त क्रमांक 1), राम चन्द्र (अभियुक्त क्रमांक 11), भगवान स्वरूप (अभियुक्त क्रमांक 13), लालता प्रसाद (अभियुक्त क्रमांक 8), भागीरथी (अभियुक्त क्रमांक 3) , बुधसे (अभियुक्त क्रमांक 9), बलजीत (अभियुक्त क्रमांक 10) और नन्हे लाल (अभियुक्त क्रमांक 14) बांका से लैस थे। अन्य साथी दल चंद (अभियुक्त क्रमांक 29) सुजा, श्री कृष्ण (अभियुक्त क्रमांक 29) से लैस थे .18), महेश (अभियुक्त क्रमांक 17), धर्मवीर

(किशोर), लालमन (अभियुक्त क्रमांक 15), चेतराम (अभियुक्त क्रमांक 24), कालीचरण (अभियुक्त क्रमांक 23), गया दीन (किशोर, मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई) , नन्हू लाल (अभियुक्त संख्या 21), कन्हाई लाल (अभियुक्त संख्या 27), नोखे लाल पुत्र राम दयाल (अभियुक्त संख्या 19) और ओम प्रकाश (अभियुक्त संख्या 16) जो अपने हाथों में लाठियाँ लिए हुए थे।

3. शिकायतकर्ता के अनुसार, राम स्वरूप (अभियुक्त संख्या 7) ने अन्य आरोपियों को शिकायतकर्ता पक्ष को मारने के लिए उकसाया। डर के मारे, शिकायतकर्ता अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागा। आरोपी पक्ष ने उनका पीछा कर उन पर अंधाधुंध हमला कर दिया और फायरिंग कर दी। जब शिकायतकर्ता पक्ष के कुछ सदस्य आरोपी पक्ष की निर्मम गोलीबारी से खुद को बचाने के लिए एक कोठरी (खेत में एक छोटा कमरा) में घुस गए, तो महिलाओं ने माया देवी (आरोपी नंबर 4), अमृति देवी (आरोपी नंबर 5) पर आरोप लगाया। और सुनीता देवी (अभियुक्त क्रमांक 6) जो अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर आई थी, उसने उसे कोठारी के खपरैल पर डाल दिया और राम स्वरूप (अभियुक्त क्रमांक 7) ने सामने की ओर से आग लगा दी और उमा शंकर (अभियुक्त क्रमांक 34) ने पीछे से आग लगा दी। ओर। पीड़ित मोती राम ने कोठारी की छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन राम स्वरूप (आरोपी नंबर 7) ने उसे गोली मार दी, जिसके परिणामस्वरूप वह आग में गिर गया। इसी तरह अन्य पीड़ित हेम राज, चुन्नी लाल और महेंद्र पाल ने कोठारी से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी गोली मार दी गई। जब आरोपी वहां से चला गया, तो शिकायतकर्ता ने महेंद्र पाल को नाले में मृत पड़ा पाया, मोती राम जली हुई हालत में कोठारी में पड़ा हुआ था। हेम राज और चुन्नी लाल के शव खेतों में मिले।

4. मामला दर्ज कर थानाप्रभारी पी.के. शर्मा (पीडब्ल्यू·14) घटनास्थल पर पहुंचे, बयान दर्ज किए और साइट योजना तैयार की। पुलिस ने तब 3 खाली कारतूस बरामद

किए, रिकवरी मेमो (एक्सटेंड का. 109) तैयार किया, मृतकों की जांच रिपोर्ट तैयार की, खून के धब्बे और सादे मिट्टी को एकत्र किया और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने आरोपी धर्मवीर क्वेनिले), माया देवी और महेश को गिरफ्तार कर लिया। सात अन्य आरोपियों जंगन लाल, नारायण, राम भरोसे, बुद्धसेन, भागीरथ, बलजीत और नन्हे लाल को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए। 17 मार्च, 2001 को पुलिस ने सात और अभियुक्तों, लालमन, काली चरण, गया दीन, नन्हू लाल, कन्हाई लाल, नोखे लाल और रामबहादुर को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लाठियाँ और बल्लम बरामद किये गये। अगले दिन अभियुक्त संख्या 7 (राम स्वरूप) सहित दस और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक 12 बोर संख्या 4236 (बंदूक) और तीन जीवित कारतूस बरामद किये गये। उमा शंकर के पास से एक 12 बोर देशी पौनिया और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. अशोक कुमार के कब्जे से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पति राम, राम चंद्र, भगवत स्वरूप और लालता प्रसाद के कब्जे से बंका बरामद किया गया। चेत राम, ओम प्रकाश पुत्र हीरा लाल के पास से लाठियां बरामद की गईं। जबकि आरोपी लाला राम को 20 मार्च 2001 को गिरफ्तार कर लिया गया था, राम स्वरूप पुत्र दल चंद, कुँवर सेन, श्री कृष्ण और ओम प्रकाश पुत्र मंशा राम ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। रामस्वरूप पुत्र डालचंद, कुंवर सेन और श्रीकृष्ण की निशानदेही पर कुछ और हथियार बरामद किए गए। जांच के बाद आरोप पत्र (एक्स. का. 120) प्रस्तुत किया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

5. एक किशोर आरोपी, गयादीन को मृत बताया गया था और दूसरे आरोपी धर्मवीर पर किशोर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था क्योंकि घटना की तारीख पर उसे भी किशोर पाया गया था। अन्य आरोपियों पर धारा 302/149 आईपीसी, धारा 148, 436/149 आईपीसी, 307/149 आईपीसी, 506 आईपीसी,

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 4 के तहत मुकदमा चलाया गया। अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से लालता प्रसाद (पीडब्लू 1), लीलावती (पीडब्लू 2), वेद प्रकाश (पीडब्लू 3) और हरि शंकर (पीडब्लू 4) प्रत्यक्ष गवाह हैं।

6. विद्वान विचारण न्यायाधीश संपूर्ण सुनवाई के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त राम स्वरूप, जगनलाल, राम भरोसे, उमा शंकर, तुलसी, नारायण, अशोक कुमार, कुँवरसेन, लालाराम, राम स्वरूप, पति राम, होरी लाल, ओम प्रकाश पुत्र मंशाराम, राम चन्द्र, भगवत स्वरूप, लालता प्रसाद, भागीरथ, बुद्ध सेन, बलजीत, नन्हे लाल, डालचंद, श्रीकृष्ण, महेश, धर्मवीर, लालमन, चेतराम; कालीचरन, गयादीन, नन्हूलाल, कन्हईलाल, नोखेलाल, राम बहादुर, ओम प्रकाश, राम स्वरूप पुत्र कन्हई लाल, श्रीमती माया देवी, श्रीमती लमरती देवी और श्रीमती सुनीता देवी धारा 147,148, 436/149, 302/ के तहत दोषी हैं। 149, 307/149 और धारा 506, आईपीसी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 4। तदनुसार, उन्हें धारा 148 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 2 साल की सजा, धारा 436/149 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा, धारा 307/149 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा, धारा 506 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 2 साल की सजा। 6 महीने की सजा और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए क्रमशः एक वर्ष का आर.आई. अभियुक्त राम स्वरूप पुत्र होरीलाल, जगन, पति राम, ओम प्रकाश पुत्र ओमांश राम, राम चन्द्र, भगवत स्वरूप, लालता प्रसाद, भागीरथ, बुद्धसेन, बलजीत, नन्हे लाल, राम स्वरूप पुत्र कन्हई लाल को दोषी ठहराया गया। आईपीसी की धारा 302/149 के तहत अपराध, विचारण न्यायालय ने उन 12 आरोपियों

के खिलाफ मौत की सजा दी। हालाँकि अभियुक्तों को दी गई सभी सज़ाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया।

7. अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ, आरोपियों ने विभिन्न आपराधिक अपीलों में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जबकि राज्य ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए आपराधिक संदर्भ को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि की और अभियुक्त संख्या 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 और 20 को छोड़कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा।. उच्च न्यायालय ने इन आरोपियों (संख्या में 12) की मौत की सजा को यह कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि उनके द्वारा किया गया अपराध दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर, राज्य और साथ ही अभियुक्तों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। जबकि राज्य ने उन 12 आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा की पुष्टि के लिए अपनी अपील को प्राथमिकता दी, आरोपियों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की।

8. हमने उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गौरव भाटिया और अभियुक्तों के विद्वान वकील श्री अनुराग सिंह को सुना है।

9. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ट्रायल जज द्वारा आजीवन कारावास में दिए गए अपराध की मौत की सजा के परिमाण पर सही ढंग से विचार करने में पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल जज ने दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का उचित परिप्रेक्ष्य में आकलन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई कि अभियोजन पक्ष ने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है। . उच्च न्यायालय अपराध

की प्रकृति और गंभीरता का उसके वास्तविक परिमाण में आकलन नहीं कर सका और मौत की सजा को आजीवन कारावास में संशोधित करने में गलती की। इस न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित कानून के आलोक में, अपराध की भयावहता, वीभत्स और जघन्य प्रकृति और अपराधियों द्वारा अपराध करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि अपराध अपराध के दायरे में आता है। 'दुर्लभ से दुर्लभतम' की श्रेणी में अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून की पूरी तरह से अवहेलना की और सजा के मामले में नरमी दिखाई, जिससे लोगों में निजी बदला लेने की भावना बढ़ेगी और बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज में अस्थिरता आएगी।

10. अभियुक्त का आपराधिक इरादा उचित संदेह से परे साबित हुआ। जब आरोपी नंबर 7 रामस्वरूप की पत्नी इमरती देवी ने सोम वती के खिलाफ ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, जिसमें आरोपी नंबर 7 की पत्नी हार गई, तो आरोपी व्यक्तियों के समूह ने आरोप लगाया कि पीड़ित पक्ष द्वारा पत्नी के पक्ष में कोई मतदान नहीं किया गया है। आरोपी नंबर 7 ने पीड़ित पक्ष को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. तदनुसार, चुनाव में उस विफलता का बदला लेने के लिए, आरोपी पक्ष को होली के त्योहार के दिन शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करने का यह एक उपयुक्त अवसर लगा, जिसमें पांच निर्दोष व्यक्तियों को बेरहमी से मार डाला गया और कई अन्य को घायल कर दिया गया। आरोपियों द्वारा गांव में उत्पात मचाकर और फिर प्रत्येक पीड़ित का पीछा कर उन्हें मौत के घाट उतारकर अपनाए गए अमानवीय व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता और मौत से कम कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए।

11. विद्वान एएजी ने आगे तर्क दिया कि घटना अचानक या अचानक नहीं घटी। इसके बजाय, नीचे की दोनों अदालतों के समक्ष यह स्थापित किया गया है कि उत्तरदाताओं ने योजनाबद्ध तरीके से अपराध किया है। जब निर्दोष पीड़ित अपनी जान

बचाने के लिए भाग रहे थे, तो आरोपियों ने उन पर हमला किया और अंधाधुंध गोलीबारी की। आरोपियों ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर कोई पीड़ितों के बचाव में आया तो उसे भी ऐसे ही परिणाम भुगतने होंगे. भय के कारण ग्रामीणों ने अपने-अपने दरवाजे बंद कर लिये और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इस प्रकार यह समाज के खिलाफ एक असाधारण मामला है जहां सामूहिक चेतना का उल्लंघन होता है अत्यधिक क्रूरता दिखाने वाले आरोपियों के शैतानी कृत्यों से समुदाय टूट गया था। ऐसे गंभीर मामलों में अंतिम सजा मौत की सजा देना न्यायालय का कर्तव्य है।

12. मच्छीसिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एसईसी 470 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट निर्णायक कारकों को पूरा करता है जैसे (i) हत्या का मकसद (ii) अपराध की असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति (iii) अपराध की भयावहता और (iv) हत्या के पीड़ित का व्यक्तित्व, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानून के शासन का अस्तित्व और मृत्युदंड लागू करने का डर उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है। अगर दूसरों की हत्या उनके हित में हो तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौत की सजा देना ही एकमात्र उपाय है जब आरोपी के कृत्य समाज के लिए एक चुनौती हैं और मामले की परिस्थितियों से पता चलता है कि यह एक निर्दयी हत्या थी और पीड़ित असहाय और असुरक्षित थे। वर्तमान मामले में आरोपियों ने बेहद क्रूर, वीभत्स, शैतानी और कायरतापूर्ण तरीके से अपराध किया और अपराधियों के कृत्य से समुदाय में अत्यधिक आक्रोश था। चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पीड़िताओं को कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और दहेज के तौर पर उनके शरीर के अंगों को बेरहमी से काट दिया गया। इसलिए, आरोपी को मौत से कम सजा देना न्याय का मजाक होगा। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को

आजीवन कारावास में संशोधित करने में त्रुटि की है और इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि अभियुक्तों पर मृत्युदंड बहाल किया जा सके।

13. अभियुक्त के विद्वान वकील ने दलील दी कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी घटना पर गलत ध्यान दिया और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पूरी तरह से दी गई है और वे सच्चाई के गवाह नहीं हैं क्योंकि यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि लगभग 35 व्यक्तियों की एक गैरकानूनी सभा एक विशेष परिवार के सदस्यों की हत्या करने के एकमात्र उद्देश्य से घातक हथियार और केरोसिन तेल लेकर एकत्रित हो। इसका सीधा सा कारण यह है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया। आम तौर पर, जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा संगठित हमला किया जाता है, तो प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का निर्धारण करना अक्सर मुश्किल होता है। अभियोजन की पूरी कहानी कमजोर आधारों पर आधारित है ताकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ झूठा मामला बनाकर उन्हें फंसाया जा सके। आईपीसी की धारा 149 के तहत सजा को आकर्षित करने के लिए 'सामान्य उद्देश्य' के सिद्धांत के महत्व को देखते हुए, निचली अदालतों ने इस तथ्य को समझने में गलती की है कि अभियोजन पक्ष उस भूमिका को स्थापित करने में विफल रहा है जो वास्तव में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई थी। जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।

14. अभियोजन की कहानी एक अन्य कारण से बेहद असंभव है कि अभियुक्तों को दी गई सजा को उचित ठहराने के लिए 'मकसद' संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है। यह एक ठोस धारणा है कि हर आपराधिक कृत्य किसी मकसद से किया जाता है। यह पूरी घटना अचानक घटी, जिसमें कई ग्रामीण गोलियों के डर से इधर-उधर भाग रहे थे, इस दौरान कुछ ग्रामीण घायल हो गए। ऐसे में किसी के लिए भी इस बात पर

ध्यान देना संभव नहीं है कि आख़िर हुआ क्या था. जिस अराजक स्थिति में कथित घटना घटी थी, उसे देखते हुए यह हास्यास्पद और समझ से परे है कि रात 8.10 बजे तक पुलिस के पास एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की जा सकी। उसी दिन, वह भी तब जब पुलिस थाना घटनास्थल से करीब 7' घंटे की दूरी पर स्थित हो. इसलिए अभियोजन की कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय है।

15. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि मोती राम का शव कोठरी के अन्दर जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ था। बाद में वही शव मोती राम का नहीं बल्कि कुन्दन लाल का निकला। अगर प्रत्यक्षदर्शी हमलावरों को पहचानने की स्थिति में होते तो वे कुंदन लाल के शव की पहचान करने में गलती नहीं करते. दस आरोपियों के खिलाफ अंधाधुंध गोलीबारी का आरोप लगाया गया था, लेकिन मोती राम और हेम राज की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनमें से प्रत्येक के शरीर पर केवल एक बंदूक की चोट थी। इन दोनों मृतकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आग्नेयास्त्र से चोट नहीं आई है। इसी तरह, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी श्रीकृष्ण और गया दीन बल्लम लेकर गए थे, लेकिन मृतकों या घायलों के शरीर पर बल्लम की कोई चोट नहीं थी। इसलिए चश्मदीदों के बयान भरोसेमंद नहीं हैं. जो प्रत्यक्षदर्शी शवों की सही पहचान भी नहीं कर सके, उनके बयानों के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों को झूठा फंसाया गया।

16. अभियुक्त के विद्वान वकील द्वारा पेश किया गया एक और तर्क यह है कि अपराध में माया देवी (अभियुक्त संख्या 4), अमृति देवी (अभियुक्त संख्या 5) और सुनीता देवी (अभियुक्त संख्या 6) की भागीदारी उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि ये तीनों आरोपी अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर आए थे और जब अन्य आरोपियों ने कोठरी में आग लगा दी तो उन्होंने उसे कोठरी के छप्पर पर डाल दिया। आरोप को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि

जब कथित तौर पर कई अन्य आरोपियों के पास घातक हथियार थे, तो होली के त्योहार के दिन इन महिला आरोपियों द्वारा केरोसिन तेल का डिब्बा ले जाना बेहद संदिग्ध है। लालता प्रसाद (पीडब्लू 1), मुख्य गवाह, ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में यह नहीं बताया। इन महिलाओं द्वारा कोठरी के छप्पर पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बारे में इसके अलावा, कुछ अन्य आरोपी नन्हू लाल, कन्हाई लाल, दल चंद, होरी लाल, नोखे लाल और राम बहादुर उम्र में बहुत बड़े हैं और ऐसे अपराध में उनकी भागीदारी भी संदिग्ध है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने आरोपियों को संदेह का लाभ दिए बिना सजा देने में गलती की थी।

17. इन अपीलों के गुण-दोष पर राय बनाने से पहले, नीचे दिए गए न्यायालयों की मुख्य टिप्पणियों पर गौर करना उचित होगा। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को मौत की सजा देते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "आरोपी व्यक्तियों को सजा के बिंदु पर सुना गया।
>
> अभियोजन पक्ष के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, आरोपी व्यक्तियों द्वारा पांच लोगों की बेरहमी से और वीभत्स तरीके से हत्या कर दी गई और जला दिया गया और सात लोगों को तेज धार वाले हथियारों और लाठियों से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गांव में प्रधान के चुनाव में हार का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस 35 आरोपियों ने शिकायतकर्ता पक्ष के साथ खूनी होली खेली। जहाँ तक मृत व्यक्तियों के शरीर पर चोटों से यह स्पष्ट है कि उनके शरीर के कुछ हिस्सों को बेरहमी से काट दिया गया है और जब पीड़ितों ने खपरैल में छिपकर खुद को बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उक्त खपरैल में आग लगा दी और जब असहाय पीड़ितों ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश

की, आरोपियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की और बांका से काट डाला। इस प्रकार, यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और इसलिए सभी आरोपी मृत्युदंड के पात्र हैं। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 1999 सीआर.एल.जे.पेज 2873 और 201 सीआर.एल.जे. पेज 1462 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

उपरोक्त के विपरीत, बचाव पक्ष के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सभी आरोपी व्यक्ति एक ही जाति के हैं और गरीब किसान हैं। आरोपियों में होली लाल, डाल चंद, नानू लाल उम्र 70 वर्ष, कन्हाई लाल उम्र 90 वर्ष, नोखे लाल उम्र 80 वर्ष और राम बहादुर उम्र 65 वर्ष शामिल हैं। इसलिए उन्हें कोई भी सजा देते समय उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

यह सही है कि सभी अभियुक्तों ने गांव के चुनाव में हार का बदला लेने के लिए राइफल, पौनिया, देशी पिस्तौल, बल्लम, सूजा और लाठी जैसे घातक हथियारों से लैस होकर असहाय और निर्दोष व्यक्तियों पर हमला किया था और उन पर उस समय हमला किया था जब वे होली का त्योहार मना रहे थे तभी दरिंदों ने की कोशिश खुद को बचाने के लिए वे खपरैल में छिप गए और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए, आरोपियों ने पहले दरवाजे तोड़ने की कोशिश की और जब वे दरवाजे तोड़ने में असफल रहे, तो आरोपियों ने खपरैल पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। जिसके परिणामस्वरूप कुन्दन लाल की जलकर मौत हो गई और जब अन्य लोग खपरैल से बाहर आए और खुद को बचाने के लिए भागे, तो आरोपियों ने उन्हें बांका से काट दिया और परिणामस्वरूप महेंद्र पाल, मोती राम, हेम राज और चुन्नी

लाल की हत्या कर दी गई। और बेरहमी से मार डाला. इतना ही नहीं लालता प्रसाद, हरी शंकर, लीलावती, गंगा राम, देवी राम, श्रीमती। किशोरी देवी एवं श्रीमती. अतर काली को भी गंभीर चोटें आईं। यह उनकी किस्मत ही थी कि उन्होंने खुद को बचा लिया, वरना आरोपियों ने उन्हें भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. इसलिए मैं अभियोजन पक्ष के इस तर्क से पूरी तरह सहमत हूं कि तत्काल मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। सभी मृतकों और घायलों पर राइफल और बांका से बेरहमी से हमला किया गया और उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। अतः मेरी राय में आरोपी राम स्वरूप पुत्र होरी लाल, जगन लाल, पतिराम पुत्र मंशा राम, रामचन्द्र, भगवत स्वरूप, लालता प्रसाद, भागीरथ, बुद्धसेन, बलजीत, नन्हे लाल और राम स्वरूप पुत्र कन्हई लाल हैं। मृत्युदंड पाने का हकदार. इन अभियुक्तों में से, राम स्वरूप पुत्र होरी लाल और जगन लाल के पास लाइसेंसी राइफलें थीं, जबकि शेष अभियुक्तों के पास बांका थे।"

18. तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने बारह आरोपियों को मौत की अत्यधिक सजा सुनाई है। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 और राम पाल बनाम यूपी राज्य (2003) 7 एसईसी 141 में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा:

"सजा देने में करुणा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह घावों को ठीक करने की अनुमति देता है। कारावास की लंबी उम्र उन्हें कारण समझने में मदद कर सकती है। समय बीतने पर वे अपने द्वारा किए गए अपराध पर विचार कर सकते हैं। इससे उनमें पश्चाताप और पश्चाताप की भावना पैदा हो सकती है। मामले की समग्र परिस्थितियों को

ध्यान में रखते हुए यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आजीवन कारावास की कम सजा के लिए कारावास पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और हमारा विचार है कि आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अपीलकर्ता न्याय के लक्ष्य को पूरा करेंगे।"

19. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, वर्तमान अपील में विचार करने योग्य मुद्दा यह है कि क्या अभियोजन पक्ष उन अपराधों के लिए सभी उचित संदेह से परे आरोपियों का अपराध स्थापित कर सकता है जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था? और यदि हां, तो क्या यह मामला "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" की श्रेणी में आता है, जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि इस क्रूर घटना के परिणामस्वरूप पांच ग्रामीणों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि राम स्वरूप (अभियुक्त संख्या 7) पूरे समय आरोपी पक्ष को पीड़ित पक्ष पर हमला करने के लिए उकसा रहा था, अन्य आरोपियों ने अपराध में भाग लिया था। जब असहाय पीड़ितों ने एक कोठारी में शरण ली, तो आरोपियों ने अपना बदला लेने के लिए कोठारी के दरवाजे काटने की कोशिश की और असफल रहे। ऐसा करने पर, उन्होंने छप्पर पर मिट्टी का तेल डाला और कोठरी को जला दिया, जिससे पीड़ित झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई।

20. डॉ. ए.पी. शर्मा (पीडब्लू 5) जिन्होंने मृतक मोती राम के शव का पोस्टमॉर्टम किया, उनकी राय थी कि मृत्यु का कारण सदमा, रक्तस्राव, मृत्यु पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप दम घुटना था। इसी तरह की राय डॉ. विमल श्रीवास्तव (पीडब्लू 6) ने भी दी थी जिन्होंने अन्य पीड़ितों के शवों का पोस्टमॉर्टम किया था। डॉ. आर.एस.

सोन, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, पी.एच.सी बरखेरा, जिला पीलीभीत (पीडब्लू 7) जिन्होंने घायल व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच की थी, उन्होंने पीड़ितों के शरीर पर कटे हुए घाव, कई खरोंचें और चोट के निशान पाए। चोटों की प्रकृति और आरोपियों के पास से हथियारों की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि यह एक बड़ी अप्रिय घटना थी और आरोपियों ने अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

21. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से, यह स्पष्ट है कि सभी आरोपी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने घातक हथियारों से लैस एक मजबूत समूह बनाया और गांव के चुनावों में अपनी हार का बदला लेने के लिए पीड़ितों पर हमला किया। आरोपी द्वारा दी गई दलील कि घटनास्थल पर आरोपी की पहचान करना मुश्किल है, जबकि अपराध में लगभग 35 लोगों की भागीदारी थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि घटना शाम 5.00 बजे हुई थी। मार्च के महीने में पर्याप्त प्रकाश में और निर्विवाद रूप से, आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लालता प्रसाद (पीडब्लू 1), लीलावती (पीडब्लू 2), हरि शंकर (पीडब्लू4) घायल चश्मदीद गवाह हैं जिनकी गवाही एक अन्य स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी वेद प्रकाश (पीडब्लू 3) के साक्ष्य से पुष्ट हुई थी। इन गवाहों ने स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में बताया कि किस प्रकार अभियुक्तों ने महेंद्र पाल, हेम राज, की हत्या की।चुन्नी लाल, मोती राम और कुन्दन लाल और गंगा राम, देवी राम, किशोरी देवी और अतर काली को चोटें आईं। इस प्रकार घटना के समय गवाहों की उपस्थिति और पीड़ितों द्वारा आरोपियों की पहचान पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

22. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ मूल्यांकन किए गए चिकित्सा साक्ष्य द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की पुष्टि करते हुए, हमें पांच ग्रामीणों की हत्या के अलावा कई अन्य लोगों को घायल करने के आपराधिक अपराध में आरोपी की भागीदारी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अभियुक्तों के कब्जे से

घातक हथियारों की बरामदगी इस घातक कृत्य में उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका की दृढ़ता से पुष्टि करती है। इसलिए, जहां तक अभियुक्तों की दोषसिद्धि का संबंध है, हमें निचली अदालतों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है, और हमारी सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्तों का अपराध साबित कर दिया है। परिणामस्वरूप, अभियुक्तों द्वारा उनकी दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील खारिज कर दी जाती है और तदनुसार, मुद्दे का उत्तर दिया जाता है।

23. अब विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध दुर्लभतम मामलों में आता है, जिसमें मौत की सज़ा का प्रावधान है। जुर्माना और क्या मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले में कोई अवैधता है।

24. कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि मृत्युदंड की सजा देना एक अपवाद है और इसे केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत, एक सामान्य नियम के रूप में मौत की सजा पारित करने के लिए अदालतों को पर्याप्त विवेक दिया गया था और जीवन की वैकल्पिक सजा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती थी और वह भी सामान्य नियम से हटने के लिए विशेष कारण दर्ज करने के बाद। . दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने उक्त नियम को उलट दिया है। आजीवन कारावास की सज़ा अब नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। इसने अदालतों के लिए विशेष कारण दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया है, यदि अंततः मौत की सज़ा दी जानी है।

25. यह प्रश्न कि क्या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, लंबे समय से न्यायालयों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक जटिल प्रश्न रहा है। इसके लिए कोई निश्चित मानदंड या सूत्र विकसित नहीं किया गया है और इसका थोपना प्रत्येक मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों पर निर्भर है, न्यायाधीश की दृष्टि और समझ को अविभाज्य पाया गया है। वाक्यांश "दुर्लभ से दुर्लभतम" को अभी भी परिभाषित किया जाना बाकी है, जबकि मानव जीवन की चिंता, सभ्य समाज के मानदंड और अपराधी को सुधारने की आवश्यकता ने न्यायालयों का ध्यान आकर्षित किया है। समान रूप से यह विचार रहा है कि मौत की सजा अपराधी के अपराध के बजाय उसके कृत्य पर आधारित होनी चाहिए। अपराध, पीड़ित और अपराधी की तुलना में सजा की आनुपातिकता का सिद्धांत न्यायालयों की सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है।

26. बचन सिंह के मामले में इस न्यायालय ने यह कहते हुए कुछ दिशानिर्देश तैयार किए हैं कि वे केवल शिक्षाप्रद हैं और संपूर्ण नहीं हैं। इस अदालत ने माना कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामला तब होता है जब समुदाय की सामूहिक चेतना इतनी सदमे में होती है कि वह न्यायिक शक्ति के धारकों से मौत की सजा देने की उम्मीद करेगी, भले ही मौत की सजा को बरकरार रखने की वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो।

27. इस न्यायालय ने कई मामलों में बचन सिंह और मच्छी सिंह के मामलों में निर्धारित दिशानिर्देशों को दोहराया और उन मामलों के बारे में विस्तार से निपटाया जो दुर्लभतम मामलों के अंतर्गत आते हैं।

28. नील कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012)5 एससीसी 766, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470 और बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 में इस न्यायालय ने माना कि अत्यधिक जुर्माना लगाया जाएगा। अत्यंत दोषी मामलों को छोड़कर मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है। मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले अपराध की परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मृत्युदंड की सजा केवल उसी मामले में दी जा सकती है जहां अदालत

इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास देना पूरी तरह से अपर्याप्त है। गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों की बैलेंस शीट तैयार करनी होगी और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

29. हरीश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (12) एस ई सी 56 में इस न्यायालय ने माना कि 'दुर्लभतम मामला' तब आता है जब एक दोषी समाज के सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा और खतरा होगा। अपराध जघन्य या क्रूर हो सकता है लेकिन 'दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में नहीं हो सकता है। यह मानने का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि आरोपी को सुधारा या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता और यह कि उसके द्वारा हिंसा के आपराधिक कृत्य जारी रखने की संभावना है क्योंकि यह समाज के लिए एक निरंतर खतरा होगा। आरोपी समाज के लिए खतरा हो सकता है और इसके शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा बना रहेगा। अपराध करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप समुदाय में तीव्र और चरम आक्रोश हो और समाज की सामूहिक चेतना को झटका लगे।

30. आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1995 एससी 264 में, इस न्यायालय ने विचार किया कि दुर्लभतम मामलों में से कौन सा मामला है और कब मौत की सजा दी जा सकती है और यह देखा गया कि हत्या के लिए प्रदान की जाने वाली सजा में से कौन सा विकल्प उचित है। किसी दिए गए मामले में यह उस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और न्यायालयों को मामले की सभी कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करने के बाद अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर न्यायिक रूप से अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि क्या अपराध के बारे में कुछ अज्ञात है जो

आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा देने की मांग करता है।

31. संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य (2010) 9 एससीसी 747 में इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि निस्संदेह, सजा का हिस्सा कठिन है और अक्सर न्यायालय के दिमाग पर काम करता है, लेकिन जहां विकल्प आजीवन कारावास और मौत के बीच होता है। सजा, विकल्प वास्तव में बेहद सीमित हैं और यदि न्यायालय स्वयं किसी एक या दूसरे को सजा देने में कुछ कठिनाई महसूस करता है, तो यह उचित है कि कम सजा दी जानी चाहिए। यह "दुर्लभ से दुर्लभतम" सिद्धांत के पीछे अंतर्निहित दर्शन है।

32. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, मच्छी सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, राज्य के विद्वान वकील ने आरोपी पर मौत की सजा बहाल करने की मांग की। इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपियों ने पीड़ितों को मारने की कोशिश की थी। जब पीड़ितों ने एक कोठरी में शरण लेकर खुद को बचाने की कोशिश की, तो उसमें आग लगा दी गई और भागने की कोशिश करने वाले पीड़ितों के साथ मारपीट की गई।

33. जहां तक आरोपी के मकसद का सवाल है, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव हारने वाली आरोपी नंबर 7 की पत्नी के पक्ष में वोट न देने के लिए ग्रामीणों से बदला लेने के लिए, आरोपी पक्ष ने पीड़ितों पर हमला किया। यह रिकॉर्ड में आया है कि घटना 10 मार्च, 2001 को हुई थी और ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव घटना की तारीख से बहुत पहले यानी घटना की तारीख से लगभग दस महीने पहले हुए थे। चुनाव के समय और घटना की तारीख के बीच लंबे समय के अंतराल को

ध्यान में रखते हुए, यह आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि आरोपियों ने चुनाव में अपने पक्ष में वोट न देने का बदला लेने के स्पष्ट उद्देश्य से पीड़ितों पर हमला किया।

34. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा अभियुक्तों को मौत की सजा देने के लिए उठाए गए अपराध की भयावहता का प्रश्न, यह एक गाँव के दो समूहों के बीच झड़प थी और इसे अनुपात में बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता है। एक आपराधिक मुकदमे में जब अभियोजन पक्ष मौत की सजा देने का मामला बनाना चाहता है, तो अभियोजन पक्ष को निस्संदेह एक बहुत ही कठिन बोझ उठाना पड़ता है। अभियोजन पक्ष को गंभीर परिस्थितियों के अस्तित्व और परिणामी परिस्थितियों को कम करने वाली अनुपस्थिति को प्रदर्शित करके इस बोझ का निर्वहन करना चाहिए। इस तरह के बोझ का निर्वहन करने में, अभियोजन पक्ष को न केवल अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे स्थापित करना होगा, बल्कि अपराध के घटित होने और गंभीर परिस्थितियों को भी साबित करना होगा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" की श्रेणी में आता है। "मौत की सज़ा देने की गारंटी देने वाले मामले"।

35. हालाँकि, जहाँ तक सजा वाले भाग का सवाल है, यहाँ ऊपर उल्लिखित कानून के मद्देनजर मृत्युदंड अब सबसे संकीर्ण क्षेत्र तक ही सीमित है। हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि आरोपियों ने अत्यंत वीभत्स प्रकृति के कृत्यों में खुद को शामिल किया। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना होगा कि आरोपी उग्र थे और बदला लेने की भावना से ही पागल हो रहे थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों के दायरे में आता है, हत्या की क्रूरता को सभी शमन करने वाले कारकों के साथ देखा जाना चाहिए। हालाँकि अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध की गई आपत्तिजनक परिस्थितियाँ अपीलकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराती हैं, लेकिन मच्छी सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, मामले की सभी कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करने

के बाद, हम उनका मानना है कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा उनके द्वारा समाज को और कमजोर बनाने वाले ऐसे आपराधिक कृत्यों की पुनरावृत्ति भी स्पष्ट नहीं है। उनके सुधार एवं पुनर्वास के लिए आशा की किरण जगी है। इसलिए, हम आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाते हैं कि यह मामला इस न्यायालय द्वारा परिकल्पित दुर्लभतम मामलों के अनुपात में नहीं आता है। अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय हमारी सुविचारित राय है कि अभियुक्त को मृत्युदंड से कम सजा दी जा सकती है। इसलिए, हमारे विचार में, विचारण न्यायाधीश द्वारा दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में संशोधित करने में उच्च न्यायालय सही था।

36. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखते हैं। परिणामस्वरूप, राज्य और अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा की गई अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

देविका गुजराल

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।